



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940
No. 46]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

समाप्ति आदेश

मामला सं. (सीबीडी) 7/ 2018

विषय : चीन जन. गण. से फ्लूओरोलास्टोमर्स (एफकेएम) के आयातों के संबंध में प्रतिकारी शुल्क संबंधी जांच।

फा सं. 6/21/2018-डीजीटीआर.—जबकि गुजरात फ्लोओरोकेमिकल्स लिमि. (जिसे यहां आवेदक या याचिकाकर्ता के रूप में उल्लिखित किया गया है) ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे यहां संबद्ध देश कहा गया है) से कुछ विशेष फ्लूओरोलास्टोमर्स (एफकेएम) (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) की आर्थिक सहायता का आरोप लगाते हुए समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित (जिसे इसके बाद नियमावली कहा गया है) सीमाशुल्क टैरिफ (आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के अनुसरण में, घेरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश के उद्दम की संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर प्रतिकारी शुल्कों को लागू करने के लिए आर्थिक सहायता-रोधी जांच की शुरूआत के लिए अनुरोध किया है।

2. ए एस सी एम के अनुच्छेद 13 की शर्तों में, नई दिल्ली में दिनांक 6 अगस्त, 2018 को चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जांच शुरूआत से पूर्व विचार-विमर्श किया गया।

3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर कथित आर्थिक सहायता की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा प्रतिकारी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लागू किया जाता, तो घरेलू उद्योग की क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होता, सीवीडी नियमावली के नियम 6 के अनुसरण में संबद्ध सीवीडी जांच आरंभ करते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 14.08.2018 की अधिसूचना सं. 6/21/2018-डीजीटीआर के अनुसार एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।
4. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पीओआई) जनवरी, 2017-दिसंबर, 2017 (12 महीने) तय की है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में पद्धतियों की जांच के लिए, अवधि में 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जांच की अवधि शामिल की गई है।
5. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के पश्चात भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को व आवेदक द्वारा उलब्ध कराए गए पतों के अनुसार ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को जांच शुरूआत की अधिसूचना की प्रतियां भेजी और उन से सीवीडी नियमावली के नियम 7 के अनुसार जांच शुरूआत अधिसूचना के जारी होने के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। ऐसे अनुरोध दायर करने के लिए अनिवार्य समय विस्तार, जहां भी जरूरी था, भी प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए।
6. प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(3) के अनुसरण में भारत में संबद्ध देश के दूतावास और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराई गई। जहां भी अनुरोध किया गया, अन्य संबद्ध पक्षकारों को आवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराई गई। भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी उनके देश से निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया।
7. प्राधिकारी ने सी वी डी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसरण में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए संबद्ध देश में समर्थ ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी।
8. जांच शुरूआत अधिसूचना और सूचना की प्रतिक्रिया में, संबद्ध देश से निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने नियतकों की प्रश्नावली के उत्तर को दायर करते हुए प्राधिकारी को उत्तर प्रस्तुत किए :
 क. मै. इनर मंगोलिया 3 एफ वानहाओ फ्लूओरो केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
 ख. मै0 सोलवे स्पेशियलिटी पॉलीमर्स (चांगशू) कं0 लिमिटेड,
 ग. मै0 सोलवे (शंघाई) कंपनी लिमिटेड,
 घ. मै0 झोंगाऊ चेनगुआंग रिसर्च इंस्टीट्यूट केमिकल इंडस्ट्री कं0 लिमिटेड,
 ड. मै0 ऊनी अलांएस लिमिटेड,
 च. मै0 डायकिन फ्लूओरोकेमिकल्स (चीन) कं0 लिमिटेड,
 छ. मै0 चेनगुआंग फ्लूओरो एंड सिलिकॉन एलास्टोमर्स कं0 लिमिटेड,
9. अनिवार्य सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजी गई। निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली उत्तर को दायर करने के द्वारा प्रत्युत्तर दिया है :-
 क. मै0 सोलवे स्पेशियलिटी इंडिया प्रा0 लिमिटेड,
 ख. मै0 निधिगंधा पोलीमर्स प्रा0 लिमिटेड,
 ग. मै0 इस्ट क्राप इंटरनेशनल
 घ. मै0 हाई-टेक ए आर ए आई प्रा0 लिमिटेड ने भी लिखित अनुरोधों को दायर करते हुए प्रत्युत्तर दिया है।

10. विशेष तथ्यों/विचारों को प्रस्तुत करने सहित जांच शुरूआत को भी स्वीकृत किया गया:-
- मै0 देवाशीष पालीमर्स,
 - मै0 डेगर सेफटी इंडिया प्रा0,
 - मै0 टेक्नो पालीमर्स इंडस्ट्रीज
11. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खोली गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया।
12. प्राधिकारी ने मौखिक सुनवाई के लिए दिनांक 08.02.2019 की तारीख निर्धारित की है।
13. तथापि, आवेदक ने अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हुए अपने दिनांक 22.01.2019 और 01.02.2019 के पत्रों के अनुसार वर्तमान जांच को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है:-
- याचिका इसलिए दायर की गई क्योंकि चीनी उत्पादकों को महत्वपूर्ण प्रतिकारी आर्थिक सहायताओं से लाभ पहुंच रहा था। चूंकि समान उत्पाद के लिए आयोजित ए.डी. जांच में दिनांक 27.12.2018 को अंतिम जांच परिणाम 18 महीनों के लिए शुल्क की सिफारिश करते हुए जारी किया गया है, घरेलू उद्योग को ए.डी. मामले के लिए निर्णायिक समीक्षा (एस एस आर) याचिका पर काम आरंभ करना है।
 - जब तक सीवीडी जांच पूरी हो जाती है, घरेलू उद्योग द्वारा एस एस आर के जरिए ए डी डी के विस्तार की मांग करते हुए एक आवेदन दायर करना होगा। यह आशंका है कि यदि सिफारिश की जाती है तो, सीवीडी शुल्क अभी भी कम अवधि के लिए लागू हो सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता को विश्वास नहीं है कि क्या प्रतिकारी शुल्कों को लागू किए जाने के अनुरोध को जारी रखना उचित होगा क्योंकि इसी समय वे ए डी मामले में एसएसआर के लिए तैयारी कर रहे थे।
 - वित्त मंत्रालय ने दिनांक 28.01.2019 को ए डी डी लागू करते हुए अधिसूचना जारी की है और यह कि वर्तमान ए डी डी दिनांक 27.07.2020 को समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता को अगस्त, 2019 तक याचिका दायर करनी है।
 - यदि आवेदक इस अनुरोध के साथ वर्तमान सीवीडी याचिका वापिस ले रहे हैं कि यदि भविष्य में परिस्थितियां ऐसी मांग करती हैं तो उन्हें इस आवेदन को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता होगी।
14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीवीडी नियमावली के नियम 16(1)(क) का पाठ निम्नानुसार है:—
- “16. जांच का समाप्त - (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना को जारी करते हुए तत्काल किसी जांच को समाप्त करेंगे यदि—
- (क) यदि प्रभावित घरेलू उद्योग से अथवा उस व्यक्ति की ओर से ऐसा करने के लिए लिखित में कोई अनुरोध प्राप्त होता है, जिसके उदाहरण पर जांच आरंभ की गई थी;”
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपरोक्त नियम एक बार घरेलू उद्योग द्वारा जांच की समाप्ति के लिए लिखित अनुरोध दायर किए जाने के पश्चात, जांच की समाप्ति के मामले में प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करते।
15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और दिनांक 27.12.2018 के अंतिम जांच परिणाम के माध्यम से 18 महीने की अवधि के लिए समान संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए उभरते हुए घटनाक्रमों और परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा अधिसूचना संख्या 6/21/2018- डी जी टी आर के अनुसार दिनांक 14.08.2018 को आरंभ की गई वर्तमान जांच को समाप्त करते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department Of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDING

New Delhi, 5th February, 2019

Termination Order**Case No. (CVD) 7/2018****Subject: Countervailing duty investigation concerning imports of Fluoroelastomers (FKM) from China PR.**

F.No. 6/21/2018-DGTR.—Whereas Gujarat Fluorochemicals Limited (hereinafter referred to as the applicant or petitioner) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Rules), alleging subsidization of certain Fluoroelastomers (FKM) (hereinafter referred to as the subject goods), from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and requested for initiation of an anti-subsidy investigation for levy of countervailing duties on the imports of the subject goods, originating in the subject country.

2. In terms of Article 13 of ASCM, pre-initiation consultations were held with the representatives of the Government of the People's Republic of China on 6th August, 2018 in New Delhi.
3. The Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No.6/21/2018-DGTR dated 14.08.2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject CVD investigation in accordance with the Rule 6 of the CVD Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged subsidization and to recommend the amount of Countervailing duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
4. The Authority considered January, 2017 – December, 2017 (12 months) as the Period of Investigation (POI). For the examination of trends, in the context of injury analysis, the periods covered included 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the period of investigation.
5. The Authority post-initiation sent copies of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification as per Rule 7 of the CVD Rules. Necessary extensions to file such submissions wherever warranted was also granted by the Authority.
6. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of the subject country in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested. The embassy of the subject country in India were also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
7. The Authority sent questionnaires to enable known producers/exporters in subject country to provide requisite information in accordance with Rule 7(4) of the CVD Rules;
8. In response to the initiation notification and intimation, following exporters / producers from subject country have responded to the Authority by filing Exporter's Questionnaire Response.
 - a) M/s Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd.
 - b) M/s Solvay Specialty polymers (Changshu) Co Ltd.
 - c) M/s Solvay (Shanghai) Co Ltd.
 - d) M/s Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd.
 - e) M/s Uni-Alliance Ltd.
 - f) M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co., Ltd.
 - g) M/s Chenguang Fluoro and Silicone Elastomers Co., Ltd.

9. Questionnaires were also sent to known importers / users of subject goods in India calling for necessary information. Following importers/users responded by filing Importer Questionnaire responses;
 - a) M/s Solvay Specialities India private Limited.
 - b) M/s Nishigandha Polymers Pvt. Ltd.
 - c) M/s Eastcorp International
 - d) M/s HI-Tech ARAI Private Limited had also responded by filing written submissions.
10. The initiation was also acknowledged including submissions of certain facts/views:
 - a) M/s Devashish Polymers
 - b) M/s Drager Safety India Pvt.
 - c) M/s Techno Polymer Industries
11. The Authority made available non-confidential version of the data/evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
12. The Authority fixed the date for Oral hearing on 08.02.2019.
13. However the Applicant has made request to terminate the present investigation vide its letters dated 22.01.2019 and 01.02.2019 citing following reasons inter alia ;
 - The petition was filed as Chinese Producers were benefitted with significant Countervailing Subsidies. Since Final Finding dated 27.12.2018 for the same product in an AD investigation have been issued recommending duty for 18 months, the domestic industry has to start working on Sunset Review (SSR) Petition for the AD case.
 - By the time the CVD investigation is completed the Domestic industry would be filing an application seeking extension of ADD through SSR. It is apprehended that the CVD duty may still be for shorter duration, if recommended. The petitioner is therefore not sure whether it would be appropriate to continue to request imposition of countervailing duties as at the same time they were preparing for SSR in AD case.
 - The Ministry of Finance has issued the notification imposing ADD dated 28.01.2019 and that present ADD will cease on 27.07.2020. The petitioner has to file petition latest by Aug, 2019.
 - The Applicant is withdrawing the present CVD petition requesting liberty to pursue the same in future in case the situation so demands.
14. The Authority notes that the Rule 16 (1) (a) of the CVD Rules read as under ;

“16. Termination of investigation. – (1) The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if –

(a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;”

The Authority notes that the aforesaid rule does not grant any discretion to the Authority in the matter of termination of investigation, once the domestic industry files a written request for termination of the investigation.
15. The Authority keeping in view the aforesaid and acknowledging the developments/ circumstances stated by the petitioner emerging on account of levy of Anti-dumping duty on same subject goods through Final Finding dated 27.12.2018 for a period of 18 months, hereby terminates the present investigation initiated on 14.08.2018 vide Notification No. 6/21/2018- DGTR.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority